

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाभी प्रभुदास देसाजी

अंक २०

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाभी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १८ जुलाई, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें २० ६
विदेशमें २० ८; शि० १४

ग्राम-शक्तिका निर्माण

[रांची जिलेमें प्रवेश करनेके पूर्व पलामू जिलेके आखिरी पड़ाव बराहीमें कार्यकर्ताओंकी सभामें किये गये प्रवचनमें से।]

आप लोग जानते हैं कि सरकारने हिन्दुस्तानकी तरक्कीके लिये अेक योजना-समिति बनायी है। उसने ५ सालके लिये अेक योजना तैयार की है। उसमें से ढाई साल तो अब खत्म हुये हैं। वह योजना अैसी है कि सरकार कुछ गांवोंके क्षेत्रको चुनती है। वहां रास्ते बनाये जायेंगे, पानीका अिन्तजाम होगा व दूसरे काम चलेंगे। ५ लाख गांवोंमें तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो बहुत भारी योजना हो जाती है, उसमें पैसेका सवाल आता है। इसलिये अुन्होंने कुछ गांव चुने हैं। योजना अच्छी है। परंतु कोयी भी योजना यशस्वी नहीं हो सकती, जब तक कि गांववालोंकी ताकतसे काम नहीं होता है। इसलिये हम चाहते हैं कि ५ लाख गांवोंमें अेकदम काम हो, क्योंकि हम गांववालोंके ही आधार पर काम करना चाहते हैं। अगर ५ लाख देहातोंमें काम करना है, तो बाहरकी मददसे काम नहीं हो सकता।

ग्राम-विकासका आधार ग्राम-शक्ति

इसलिये सर्वोदयमें माननेवालोंका विचार है कि गांवकी ताकतसे काम होना चाहिये। गांवमें ताकत नहीं है सो बात नहीं। गांवमें श्रम-शक्ति है, उसीसे पैसा निर्माण होता है। गांवकी जरूरतकी सारी चीजें गांवमें ही पैदा हो सकती हैं। गांवमें कपड़ा बन सकता है, मकान बन सकते हैं। जिस पर भी जो थोड़ीसी मदद बाहरसे चाहिये, वह मिल सकती है। जिस तरह बहुत सारा काम गांवकी अपनी निजकी शक्तिसे होना चाहिये। गांवकी खुदकी ताकत जब बढ़ेगी, तभी गांवमें स्वराज आवेगा। नहीं तो हर बातके लिये सरकारकी तरफ देखना शुरू करें, तो पुराने राजाओंके जमानेमें जैसा होता था वैसा ही होगा। उस समय राजा अच्छा हुआ तो प्रजाकी हालत अच्छी रहती थी। जिस तरह राजा पर सारा दारोमदार था। यह गुलामीकी हालत खत्म हो, इसलिये तो हरअेकको वोटका हक दिया गया। लेकिन वोट देनेसे ही स्वराज मिला, यह नहीं हो सकता है। जब तक हम अपने परिश्रमसे अपने गांवको नहीं सजाते, तब तक सिर्फ वोट देनेसे हम जैसेके तैसे रह जाते हैं। फिर तो यह होगा कि राजाका नाम गया और उसके बदले मंत्रीका नाम आ गया। हमें सच्चा स्वराज मिला ही नहीं, पुराना राज ही अेक दूसरे ढंगसे चालू हुआ है।

बंटवारा भी ग्राम-शक्तिसे ही

इसलिये हम हरअेक गांवसे जमीन मांगते हैं। वैसे तो सरकार भी कानूनसे जमीन ले सकती है। परंतु हम इसलिये धूमते हैं कि हम चाहते हैं कि जो जमीन देंगे, उनको हम अपने कार्य-कर्ता बनायेंगे। जमीन देकर छुट्टी पाना नहीं, जमीन देना यानी सेवाका व्रत लेना है। बेजमीनकी जमीनके साथ-साथ और भी मदद

देनी होगी। यह सब कौन करेगा? गांववालोंमें से ही जो जमीन देंगे, वे और मदद देंगे। इसीलिये तो हम कहते हैं कि मुझे हर गांवके हरअेक किसानसे दान-पत्र चाहिये। किसी गांवसे ९९ फीसदी दान-पत्र हासिल हुये और अेक भी कम रहा, तो हम कहेंगे कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ। क्योंकि गांवके बेजमीन लोगोंकी जिम्मेवारी हरअेक गांववालेकी है, यही हम समझाना चाहते हैं। धर्मका आचरण हरअेकको करना होता है, गांवको स्वर्ग बनाना हरअेकका कर्तव्य है, इसलिये हम जमीनका बंटवारा ग्राम-शक्तिसे ही करना चाहते हैं।

ग्राम-शक्ति ही समस्त प्रवृत्तियोंका स्रोत

अकसर लोग मुझसे पूछते हैं कि जमीन तो दी जा रही है, परंतु और मदद कौन देंगे? तो हम कहते हैं कि जो जमीन देंगे वही और मदद भी देंगे। हम सरकारका मुंह नहीं देखते रहेंगे। हमें अितनी जमीन सरकारने थोड़े ही दी है। जमीन तो लोगोंने दी है। इसलिये बोनके वास्ते अेक आये और काटनेके वास्ते दूसरा, यह नहीं होगा। जो बोयेगा, वही काटेगा; जिस तरह हम जमीनका बंटवारा और उसके साथ-साथ ग्रामोद्योग और नयी तालीम सब चलाना चाहते हैं। तालीमके लिये हम सरकार पर भरोसा नहीं रखना चाहते हैं। सरकार स्कूल खोलती है, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन हम तो हर गांवमें बिना पैसेके स्कूल खोलना चाहते हैं। वह अेक घण्टेका स्कूल होगा। गांवका जो पढ़ा-लिखा मनुष्य हर रोज अेक घण्टा पढ़ायेगा, उसके लिये उसे तनख्वाह नहीं दी जायगी। उसे साल भरमें थोड़ासा अनाज दिया जायगा। वह दिन भर अपना धंधा करेगा और अेक घण्टा पढ़ायेगा। वैसे ही अगर गांववाले चाहते हैं कि गांवमें पोस्ट ऑफिस खुले, तो खुल सकती है। गांवके लिये किसी अेक बच्चेको तैयार करके डाक लानेके लिये पोस्ट ऑफिसके गांव तक भेजा जाय, तो गांवमें हर रोज डाक आ सकती है। इसी तरह गांववाले अपना दवा-खाना भी गांवमें खोल सकते हैं। औषधिके लिये पैसा परदेश भेजना गलत है। हम चाहते हैं कि गांववाले मिलकर गांवमें अेक छोटासा वनस्पतिका बगीचा लगावें और वनस्पतिका ताजा रस बीमारोंको दें। यह सबसे बेहतर तरीका है। उसी तरह खादके लिये भी गढ़ बनाये जायें और मनुष्यके मल-मूत्रका खाद बनाया जाय। जिस तरह गांववाले अपनी ताकतसे सब कुछ कर सकते हैं।

उसके बाद जो संपत्तिकी थोड़ीसी मदद जरूरी है, वह गांवमें ही संपत्ति-दानके जरिये मिल सकती है। गांवमें कम-से-कम ४-५ अैसे व्यक्ति निर्माण हों जो अपनी संपत्तिका छठा हिस्सा गांवके लिये दान दें। जिस तरह गांववालोंके सहयोगसे सब कुछ हो सकता है। यही बात न्यायके लिये भी लागू होती है। अब तक न्यायके लिये लोग दूरकी कत्रहरियोंमें जाते हैं, जिसमें पैसे और समयकी बर्बादी होती है। हम तो चाहते हैं कि गांवके सज्जन लोगोंकी रायसे

ही झगड़े मिटाये जायें। ये लोग आज अंकके बाद अंक अपूरकी कचहरीमें जाते हैं, और आखिरी कचहरीमें तुम्हारे अनुकूल फैसला नहीं हुआ तो क्या करोगे, यह सवाल पूछे जाने पर कहते हैं कि तब भगवानका नाम लेंगे। तो जब आखिरमें भगवानका नाम लेना ही है, तब पहले ही क्यों नहीं लेते।

ग्राम-राज्यका अर्थ

यह सर्वोदयका विचार है। गांवके बाहरकी ताकतमें भरोसा रखकर बैठना गलत है। ग्राम-राज्यका मतलब यह है कि हम दूसरे किसीके कंधों पर नहीं बैठेंगे। आज स्वराज तो आया है, परंतु गांवों पर शहरोंकी सत्ता चलती है, और सरकारी योजना तो ऐसी बनी है कि जिस तरह मां-बाप अपने बच्चोंकी फिक्र करते हैं, वैसे ही सरकार जनताकी फिक्र करेगी। जो मां-बाप होते हैं, वे सब बच्चोंकी समान फिक्र करते हैं। परंतु सरकार सबके लिये काम नहीं कर सकती है। जिसलिये चन्द गांव चुने जाते हैं। किसी भी घरमें ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चोंको खिलाया जाता हो और कुछको भूखों मरने दिया जाता हो। हमारा ढंग ऐसा होना चाहिये कि हम सबकी अंक साथ सेवा करें। जैसे बारिश सारे हिन्दुस्तानमें अंक साथ होती है तो १५ दिनोंमें सारे हिन्दुस्तानको भिगाती है, उसी तरह हर गांवमें बूंद-बूंद मदद मिलनी चाहिये। सरकारी योजनामें ऐसा होता है कि कुछ गांवोंको ही मदद मिलती है। सर्वोदयके मानी है कि हर गांवके हर घरमें काम हो। हम मानते हैं कि हर घर हमारी बैंक है। हर घरमें जो पैसा, ताकत और अकल पड़ी है, वह सब हमारी है। आजकल हमारी सरकारके जो बैंक होते हैं, वे तो १०-५ ही होते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि हर घरमें और हर दिमागमें हमारी बैंक है। हमें सिर्फ समझनेकी देरी है।

गीता कहती है 'बुद्धरेत् आत्मना आत्मानम्'—अपना बुद्धार खुद करना पड़ता है। जो मरेगा वही स्वर्ग देखेगा। स्वर्ग देखना चाहते हो, तो मरनेकी तैयारी करो। गांव सुखी हो, आजाद हो, यह चाहते हो, तो अपनी ताकतसे काम करो। फिर सरकारकी भी मदद मिलेगी और धीरे-धीरे सरकार ही खत्म हो जायगी। गांवके टैक्सका ९९ फीसदी पैसा सरकार-गांवको ही दे देगी। उस हालतमें लोग टैक्स बढ़ानेके लिये भी तैयार होंगे। आज तैयार नहीं हैं, क्योंकि उस गांवका पैसा उस गांवमें खर्च नहीं होता है। आज सरकार भी चाहती है कि लोगोंके सहयोगसे काम हो, परंतु उसे सहयोग नहीं मिल रहा है। क्योंकि उसकी योजनामें गरीबोंको सीधी मदद नहीं मिलती है। जिस गांवमें अधिक जमीन मिली है, उस गांवमें ग्रामराज्यकी योजना बनानी होगी। आज बाहरसे सरकारी अफसर गांवमें जाते हैं, वैसे हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दान देनेवाला दाता ही कार्यकर्ता बने। वे अपने घरका खायेंगे और हमारा काम करेंगे। जिससे उन्हें बिज्जत मिलेगी। आप अपनी लड़की किसीको देते हो, तो उसके भरण-पोषणकी फिक्र भी आपको करनी होती है। उसी तरह जिसे आप जमीन दोगे, उसे दूसरी मदद देनेकी जिम्मेवारी भी आपकी ही है। आप परोपकार करना चाहते हो और खाना खिलाते हो, पर पानी नहीं पिलाते तो यह भी कोजी धर्म है? हम चाहते हैं कि हर गांवसे १० दानपत्र मिलें। जिसका मतलब है कि हर गांवमें हमें कमसे कम १० कार्यकर्ता मिलेंगे। बाहरकी मदद पर निर्भर रहोगे और अमरीकासे भीख मांगोगे, तो अमरीकाकी मददके साथ उसकी सत्ता भी आ जायगी। जिसलिये हम चाहते हैं कि गांवकी ही शक्तिसे काम हो।

दान देना सेवाका व्रत लेना है। जिस तरह हम मानते हैं कि जिन्होंने हमें वाप दिया, जिन्होंने गांवकी सेवाका व्रत लिया।

जिसलिये आप लोग दबावसे दान मत लो, क्योंकि आप दबावसे जमीन ले सकते हैं, पर जबरदस्तीसे दाताको कार्यकर्ता नहीं बना सकते। लेकिन हम तो चाहते हैं कि दान देनेवालेके मनमें परोपकारकी भावना निर्माण हो और वह गांवका सेवक बने।
('भूदान-यज्ञ विहार' से)

छोटे समाजकी खूबियां

जिसने पिछले ५० सालके इतिहास पर गहरा विचार किया होगा, वह जिस नतीजे पर नहीं पहुंचेगा कि पश्चिमी सभ्यताका अच्छे जीवनसे थोड़ा भी नजदीकका संबंध है। पिछले दो विश्वयुद्ध, सामूहिक बेकारीकी लंबी अवधियां, वाम और दक्षिण पंथी ताना-शाहियोंके कठोर और निर्मम दमन, अवांछनीय लोगोंको सामूहिक रूपमें जबरन पार्टियोंसे निकाल देना और उनकी हत्या कर डालना, बड़े-बड़े जनसमूहोंका एक देशसे दूसरे देशमें स्थानांतर और बड़े-बड़े जनसमूहोंको नजरबन्द कैम्पोंमें बन्द करके उनसे जबरन काम लेना—सब ऐसी सभ्यताके प्रमाण हैं, जिसने अपना प्रभाव और प्रतिष्ठा खो दी है और जो आत्मनाशकी ओर बढ़ रही है।

आज पश्चिम तिहरे डरका शिकार हो रहा है:—बाजारोंको खोने और आर्थिक तंत्रके टूटनेका डर, साम्यवादका डर और तीसरी लड़ाईका डर। नतीजा यह है कि दिनोंदिन अधिक मात्रामें उसकी धनराशि शस्त्रास्त्र बढ़ानेमें खर्च हो रही है। फिर भी अिनमें से कोजी भी डर दरअसल नहीं रहना चाहिये; लोगोंके मनमें वे इसीलिये बैठ गये हैं कि मनुष्यने सत्य पर और जिस तरह खुद अपने पर काबू खो दिया है। जिस काबूको वह फिरसे कैसे पा सकता है?

हमारे युगके लिये अंक ऐसी नयी जीवन-पद्धतिकी जरूरत है, जो सम्पूर्ण मानवका विचार करे—रोटी पर जीनेवाले आर्थिक मानवका और सत्य, भ्रातृभाव, सेवा, स्वार्थत्याग, चिन्तन-मनन, स्नेह, धर्म और प्रेम पर जीनेवाले आध्यात्मिक मानवका।

अस नयी पद्धतिमें अिन तीन महत्त्वपूर्ण अधिकारों या मूल्योंका समावेश होना चाहिये: हरअंकके दैनिक श्रममें जिम्मेदारीकी भावना और सर्जक अवसर तथा जिस समाजमें हम जीते हैं उसके साथ हमारा सजीव सम्बन्ध। हरअंक समाजको अपने सदस्योंको ये अधिकार देने चाहिये, ताकि उसके हर सदस्यको सर्जक काम करनेका अवसर मिले और अपनी शक्तियोंका पूरा-पूरा अुपयोग करनेका संतोष प्राप्त हो।

हमारा जमाना जिस सत्यको भूल गया है कि मनुष्य अंक सामाजिक प्राणी है, जिसका जीवन अपने समाजके साथ सजीव और अुत्पादक कामका संबंध रखनेसे ही सार्थक हो सकता है। मनुष्यका कामधंधा, उसके व्यक्तित्व और परिश्रमका गुण, और उसके सामाजिक संबंधोंकी सजीवता तीनों साथ-साथ रहते हैं; वे साथ-साथ विकास करते हैं और साथमें ही उनका पतन होता है।

अगर हम विशाल पैमानेके अुद्योग-धंधों और विशाल पैमानेके समाजोंको जन्म देनेवाली प्रक्रियाके साथ औद्योगिक विशेषज्ञताकी प्रक्रियाको जोड़ें (और ये दोनों चीजें साथ-साथ ही चलती हैं), तो हम देखेंगे कि अिन दोनों प्रक्रियाओंने कुशल कारीगरोंको यंत्रोंमें बदल डाला है और नागरिकोंको केवल कर चुकानेवाले बना दिया है, और संयोगवश सर्वसत्ताधारी राज्यकी नींव डाली है।

जिस हालतको बदलनेके लिये हमें समाजको फिरसे क्रियाशील बनाना होगा और मानवको फिरसे उसकी बुनियादी स्वतंत्रतायें और अधिकार देने होंगे। जिस ध्येयको सिद्ध करनेका अंक मार्ग यह है कि खेती और अुद्योगों पर निर्भर करनेवाले छोटे-छोटे समाजोंकी स्थापना की जाय, जिनमें हर व्यक्ति अंक जिम्मेदार कामगार और नागरिक माना जाता है, जिनके साथ हर व्यक्ति सजीव

संबंध रखता है और जो अपने संबंधों (गिल्ड्स), कौंसिलों या दूसरी अंसी योग्य संस्थाओंके जरिये अपने आर्थिक और राजनैतिक जीवन पर नियंत्रण रखते हैं।

इतिहासमें जिसके काफी प्रमाण मिलते हैं कि छोटे और अधिकतर अपना शासन खुद चलानेवाले समाजोंमें ही कारीगरी कुशलताकी चरम सीमाको पहुंचती है और नागरिकता संस्कृति तथा भव्यताके सर्वोच्च शिखर पर जा चढ़ती है। किसी व्यापारीके लिये पैदा करनेके बजाय किसी उपभोक्ता, पड़ोसीके लिये पैदा करना कहीं ज्यादा संतोषप्रद होता है, क्योंकि उससे आदर और सद्भावनाका स्थायी संबंध कायम हो जाता है। अंसी ही हालतोंमें आदमी श्रममें अपनी सारी शक्ति और योग्यता लगा देता है, साथ ही अपने घर और उसके आसपासके जीवनसे उसका सीधा और आत्मीय संबंध बना रहता है, जो खूब आदर और पसन्द करने लायक है। यह अंक अंसा पुरस्कार है, जिसे मनुष्य अपने श्रमके बदलेमें मिलनेवाले नकद पैसेसे ज्यादा महत्त्व देता है।

समाजकी अल्पता और मानवकी संपूर्णतामें बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अंक छोटी सामाजिक अिकाओंमें हर सदस्य उसका सारा कामकाज समझ सकता है, यह जान सकता है कि वह कैसे चलता है और उसके लिये कौन कौन जिम्मेदार हैं, और किसी भी प्रकारकी प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले हर आदमीसे सम्पर्क रख सकता है। इसलिये अंसे समाजके सारे कामकाज सजीव और घरेलू जैसे लगते हैं, क्योंकि उनका संबंध अंसी बातोंसे होता है जिनका समाजके हर आदमीको ज्ञान होता है।

बड़े समाजके बनिस्वत छोटे समाजमें सर्जक और भ्रातृभावपूर्ण व्यक्ति बनना, या सोचना और चिन्तन करना कहीं ज्यादा आसान है। क्योंकि उसमें परम्परा, आदत और अपने पड़ोसियोंका गहरा ज्ञान आपसी व्यवहार और सहयोगका रास्ता खोल देता है। इस तरह, जैसा कि लुडी ममफोर्डने कहा है, “२००० आदमियोंके २५ दल जितना काम कर सकते हैं, अतना अंक जगह अिकट्ठे हुये ५० हजार लोग साथ मिलकर नहीं कर सकते।” अन्होंने आगे कहा है: “तानाशाह लोगोंकी भीड़-भाड़को पसन्द करते हैं और उनके लिये बड़े-बड़े थियेट्रों और सभागृहोंका प्रबन्ध करना चाहते हैं। भीड़ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, अतना ही उसका काम ज्यादा खोखला होगा।” (‘दि कल्चर ऑफ सिटीज़’)

बड़े शहरमें उसके जीवनकी रफ्तार अच्छी तरह चलती रहे, जिसके लिये हर बातकी कुर्बानी करनी पड़ती है। उसमें व्यक्ति रेतके अंक दानेकी तरह बन जाता है। फिर भी उसमें शहरकी आत्मा जैसी कोअी चीज नहीं होती।

छोटे समाजोंमें हरअंक आदमीके काम और उसकी योग्यताका सबको परिचय हो जाता है। वहां व्यक्तियोंका ही महत्त्व होता है और वे ही हरअंककी दिलचस्पीके केन्द्र होते हैं। कोअी आदमी जो कुछ करता है, उसकी तरफ ज्यादा लोगोंका ध्यान जाता है; और अगर कोअी अपना काम अच्छी तरह करता है, तो उसकी ज्यादा लोग कदर करते हैं। यह अंक अंसा सत्य है, जो हरअंकको अच्छेसे अच्छा काम करनेकी और सचाओ व अीमानदारीसे जीवन जीनेकी प्रेरणा देता है।

यहां में मध्ययुगकी तरफ लौटनेकी दलील नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके कुछ मूल्योंको फिरसे प्राप्त करनेकी दलील जरूर करता हूं—वे मूल्य जिन्हें हमने आधुनिक अुद्योगवादकी तरफ अपनी खतरनाक यात्रामें खो दिया है। हरअंक युगकी अपनी-अपनी बुराइयां, कमजोरियां, प्रलोभन और असफलतायें होती हैं और गिल्ड-युग भी जिसका अपवाद नहीं था। लेकिन कुछ अंसे मानव-अधिकार और मूल्य हैं, जो हर युगमें हर समाजके

अभिन्न अंग होने चाहियें। औद्योगिक क्रान्ति आज इसीलिये बदनाम है कि उसने धन और सत्ताप्राप्तिकी बेतहाशा दौड़में अिनमें से कअी महत्त्वपूर्ण अधिकारों और मूल्योंकी कुर्बानी कर दी है।

गिल्ड-युगमें हर गांव और हर देहाती शहरका अपना चारित्र्य, अपना गुण और अपनी सुन्दरता थी। अुनकी तुलनामें हमारे आजके औद्योगिक शहर कुरूपता, नीरसता और अशिष्टताके बड़े घाम मालूम होते हैं। श्री जी० अेम० ट्रेवीलियनने अपने अुत्तम ग्रन्थ ‘अिंग्लिश सोशल हिस्ट्री’ में अिन दोनोंकी बड़ी अच्छी तुलना की है:

“बिना किसी योजनाके अनाप-शनाप बढ़नेवाले आधुनिक शहरमें न तो कोअी सौन्दर्य होता है और न किसी तरहका आकर्षण; वह मनुष्यकी आत्माका हनन करनेवाला अंक पिंजड़ा ही है। हमारे द्वीपका पुराना ग्रामजीवन या प्राचीन और मध्यकालीन युरोपका शहरी जीवन जिस तरह आंखोंके जरिये लोगोंकी कल्पनाको अपील करता था, वैसे आधुनिक अिंग्लैंडका शहरी और ग्रामजीवन नहीं करता। . . .” लेखक आगे कहता है कि अिन हालतोंमें मानव-व्यक्तित्वका क्रमिक स्तर (ग्रेज्युअल स्टेन्डर्डअिजेशन) कायम करनेकी शुरुआत हो गयी है।”

दो और मूल्योंका मुझे यहां जिक्र करना चाहिये: पड़ोसी धर्मका पालन और कुदरतका प्रभाव। विशाल मानव-समुदायोंमें, जहां लोगोंके आपसमें कोअी सजीव या सक्रिय सम्बन्ध और मूल्य नहीं होते, आध्यात्मिक अलगाव और भूखका जो अनुभव करना पड़ता है, उससे ज्यादा दुःखदाओ और करुण कोअी बात नहीं है।

खेती और अुद्योगों पर आधार रखनेवाले छोटे समाजका दूसरा मूल्य है कुदरतके साथ गहरा संबंध, क्योंकि कुदरत आज भी मनुष्यका अुत्तम शिक्षक और उसके आध्यात्मिक सन्तुलनको कायम रखनेवाला शक्तिशाली साधन है। कुदरत आदमीमें निरीक्षणकी, चिन्तन और मननकी आदत बढ़ाती है, और ये गुण दृढ़ चारित्र्यको जन्म देते हैं।

सम्यताओंका नाश तभी होता है, जब वे अश्वर्यवान और शक्तिशाली हो जाती हैं। छोटी परिश्रमी और दिन-रात काममें लगी रहनेवाली सम्यताओंका कभी नाश नहीं होता। जब रोम गुलामोंके परिश्रम पर खड़ा रहनेवाला शक्तिशाली साम्राज्य बन गया और सहाराकी सारी पैदावारको राक्षसकी तरह निगलकर असे रेगिस्तानमें बदलने लगा और जब उसने अपनी उपजाऊ धरतीके दलदल और अूसर भूमिमें बदल जानेकी परवाह नहीं की, तभी उसकी अूंची सम्यताका पतन होने लगा और अन्तमें वह नष्ट हो गयी।

क्या हम इससे कोअी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? सारे विश्वकी सत्ता हथियानेके लिये दुनियाकी महाशक्तियोंमें जो संघर्ष आज चल रहा है, उसमें पास और दूरके पूर्वीय देशों और अफीकाकी क्या हालत हो गयी है? दुनियाकी अधिकतर धरतीकी खनिज संपत्ति चूस ली गयी है, फिर भी पश्चिमकी मांग बढ़ती ही जा रही है।

छोटे समाजके अुत्पादक संबंधोंमें ही मनुष्य-जातिकी आशा निहित है, न कि विशाल राज्यके यांत्रिक समाजमें; इसलिये आजसे मनुष्यकी सारी प्रतिभाका अुपयोग यहां और दुनियामें हर जगह अंसा ही समाज कायम करनेमें होना चाहिये।

विल्फ्रेड वेलांक

[‘दि ओर्चाईड ली पेपर’, नं० ५ से संक्षिप्त]
(अंग्रेजीसे)

हरिजनसेवक

१८ जुलाई

१९५३

न्याय और शासन-विभाग

अंग्रेज प्रजाने जिस लोकशाहीका विकास किया, उसका यह बुनियादी सिद्धान्त माना जाता है कि राज्यके न्याय और शासन-विभाग अलग-अलग और स्वतंत्र होने चाहिये। लेकिन दोनों विभागोंके अलग होनेका यह मतलब हरगिज नहीं कि दोनोंके बीच कोई मेल न हो; क्योंकि उन दोनोंकी हस्ती ही जिसलिये है कि वे मिलकर जनताके कल्याणका काम करें। फिर भी न्याय-विभाग अपना काम ठीक ढंगसे कर सके, इसके लिये यह जरूरी माना गया है कि वह स्वतंत्र रहकर काम करे और शासन-विभाग उस पर कोई काबू न रखे। लेकिन जनहितकी व्यापक दृष्टिसे दोनोंके बीच संबंध और मेल तो होना ही चाहिये।

न्यायासनकी जिस प्रकारकी स्वतंत्रतामें अंग्रेज प्रजाका विश्वास होते हुये भी भारतमें उसने जो साम्राज्य स्थापित किया, उसमें उस प्रथाको पूरी तरह नहीं अपनाया। असा करनेसे यहाँ अपनी हुकूमत चलानेमें उसे आसानी होती थी; गोरोंका हाथ ऊपर रह सकता था; और मौका आने पर न्यायदृष्टिको अंक और रखकर अंग्रेजी हुकूमतकी रक्षामें शासन-विभागको बड़ी सुविधा होती थी।

यह चीज बुरी है, असा हमारे वजुर्ग नेताओंने बहुत पहलेसे समझ लिया था। इसके फलस्वरूप अपनी स्थापनाके समयसे ही कांग्रेस लगातार यह प्रस्ताव पास करती रहती थी कि शासन और न्याय-विभाग अलग और स्वतंत्र होने चाहिये। लेकिन अपनी हुकूमतकी नींव पर ही प्रहार करनेवाले जिस सुधारको भला अंग्रेज सरकार कैसे मानती ?

अब हमारे देशमें विदेशी हुकूमत नहीं रही। स्वतंत्र भारतका विधान बना, जिसमें एक मूलभूत आज्ञा (धारा ५०) यह की गयी है कि भारतके राज्य अिन दो विभागोंको एक-दूसरेसे अलग करनेके लिये कदम अुठावें। आनन्दकी बात है कि विधानके जिस आदेशका बम्बयी-सरकारने सबसे पहले पालन किया। इसके लिये वह हमारे धन्यवादकी पात्र है।

जिस महीनेकी पहली तारीखको यह घोषणा की गयी कि अबसे बम्बयी राज्यमें न्याय और शासन-विभाग अलग-अलग रहेंगे। असा करके बम्बयी राज्यकी सरकारने लोकशाहीमें अपनी निष्ठा जाहिर की है और शासन तथा न्यायतंत्रके लिये लोकशाही ढंग पर विकास करनेका रास्ता खोल दिया है।

जिस परिवर्तनसे अिन दोनों विभागों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयी है। अंग्रेजी राज्यमें पड़ी हुयी आदतको मिटाकर अुन्हें सच्ची प्रथाकी नींव डालनी होगी। दोनों विभागोंको जनहितका खयाल रखकर अपना काम मेलजोल और मिठाससे करना सीखना चाहिये। क्योंकि अन्तमें तो दोनों विभागोंकी हस्ती प्रजाके भलेके लिये ही है। अभी तक शासनतंत्रसे दबा हुआ न्याय-विभाग नयी मिली हुयी आजादीकी लहरमें बह न जाय; अुसी तरह न्यायको दबाकर काम करनेकी आदतवाला शासन-विभाग भी जिस कुटेवसे बचनेका हमेशा ध्यान रखे। वना दोनों विभाग प्रजाहितके काममें लगनेके बजाय — जो अुनका सच्चा धर्म है — आपसमें लड़ने लगेंगे।

जिस परिवर्तनके आरंभके अवसर पर बंबयीके मुख्यमंत्रीने रेडियो पर भाषण करते हुये कहा कि :

“मुझे विश्वास है कि जिस सुधारको अुसके सच्चे अर्थमें समझा और स्वीकारा जायगा। हमारे विधानने न्याय-विभागकी स्वतंत्रता पर अवश्य जोर दिया है, लेकिन सत्ता-विभाजनके

सिद्धान्तके चरम स्वरूपको स्वीकार नहीं किया है; और कुछ विधानोंमें गृहीत नियंत्रणों और सन्तुलनोंकी पुरानी राजनीतिको छोड़ दिया है। ‘विभाजन’ यह कड़ा शब्द है। लोकहितकारी राज्य सत्ताके विभाजनसे नहीं चलाया जा सकता; वह तभी चलाया जा सकता है, जब राज्यके तीन मुख्य विभाग — धारासभा, शासन-विभाग और न्याय-विभाग — केवल स्वतंत्रताके लिये ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा दर्जे और अवसरकी समानताके लिये भी आपसी सहयोगसे काम करें। हमें धारासभाके सदस्योंका नहीं धारासभाओंका, मंत्रियोंका नहीं शासनतंत्रका, न्यायाधीशोंका नहीं बल्कि न्याय-विभागका विचार करना है। अिन विभागोंको अुनमें सत्ताके स्थानों पर बैठे हुये सारे अस्थायी व्यक्तियोंसे अलग करके देखना चाहिये। सच पूछा जाय तो कानून बनानेमें, अुनका अमल करनेमें और अुनका अर्थ करनेमें अिन व्यक्तियोंको भारतकी जनता द्वारा तैयार किये गये विधानकी मर्यादामें रहकर और जनताकी अिच्छाके मुताबिक काम करना चाहिये। दो अलग-अलग कार्योंको जोड़ना बुरा हो सकता है, लेकिन सत्ताका गोलमाल अुससे भी ज्यादा बुरा है। जिसलिये यह कहनेकी जरूरत नहीं कि अिन दो कार्योंको अलग करनेका अर्थ अुनके बीचका संबंध तोड़ देना नहीं, बल्कि लोकसेवाके समान अुद्देश्यके लिये अुस संबंधको ज्यादा मजबूत बनाना है।”

जिस महाप्रसंग पर बम्बयी हायीकोर्टके न्यायाधीशोंने राज्यके मंत्रि-मंडलको भोजनके लिये आमंत्रित किया। अुस अवसर पर बोलते हुये प्रधान न्यायाधीशने बम्बयी राज्यमें सबसे पहले जिस सुधारके लिये मुख्यमंत्रीको धन्यवाद दिया और जिस तरह लोकशाहीमें अपनी निष्ठा जाहिर करनेके लिये अुन्हें बधायी दी। अपने मातहत आनेवाले न्याय-विभागके संबंधमें प्रधान न्यायाधीशने कहा कि यह विभाग भी प्रजाके हितके लिये ही है और अिसे भी लोकहितकारी राज्यके आदर्शकी रक्षा करनी है। अुन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशसे भी भूल हो सकती है, क्योंकि वह भी आखिर अिनसान ही है। लेकिन अुसका पद — राज्यका न्यायासन आदरणीय है, और वह स्वतंत्रतासे काम कर सके, तो ही लोकशाहीके सिद्धान्तोंका पालन करनेवाले राज्यके कानून-कायदोंका लाभ जनताको पहुंचा सकता है।

जिस शुभ आरम्भके समाचार अखबारोंमें आ रहे थे, अुन्हीं दिनों ये समाचार भी मिले कि एक शराब पीनेवालेको नीचेकी अदालतने जो सजा दी थी, अुसकी अपील पर फैसला देते हुये प्रधान न्यायाधीशने कहा कि न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटोंका सरकारकी नीतिसे कोई संबंध नहीं। अुन्हें तो जो कानून जैसा हो अुसका अुसी रूपमें अमल करना है। जिस अपीलकी अुहकीकत यह जाननेमें आयी है कि एक शस्त्रको शराब पीनेके गुनाहमें ३ माहकी कैद और ५०० रुपये जुर्मानेकी सजा दी गयी थी। अुस आदमीने शेरान्स जजके यहां अपील की। अुसमें सजा बहाल रखते हुये जजने कहा कि शराबबंदीकी नीति अब आगे बढ़ी है, जिसलिये गुनहगारको (कानूनकी ९२ वीं धाराके मुताबिक) राहत देना ठीक नहीं। जिसकी अपीलमें हायीकोर्टने अुपरोक्त बात कही और सजाको रद्द करते हुये बताया कि अगर पहले गुनाहके लिये राहत देनेकी धारा मौजूद है तो गुनहगारको राहत दी जानी चाहिये।

जिस फैसलेमें दो-अंक बातें ध्यानमें रखने जैसी हैं : एक तो यह कि शराबबंदी सरकारकी बनायी हुयी कोयी अैसी-वैसी शासन-संबंधी धारा या नीति नहीं है। जो विधान न्याय-विभागको शासन-विभागसे अलग करनेकी आज्ञा देता है, अुसी विधानकी दूसरी अंक आज्ञा शराबबंदी भी है। जिसलिये जब न्यायासन अुसे ध्यानमें लेता है, तो वह विधानमें बतायी गयी नीति और लोकहितकारी राज्यके

आदर्शको मान देता है, जो कि शासन-विभाग, न्याय-विभाग और धारासभा तीनोंका फर्ज है।

दूसरी बात यह कि आज लोकमत शराबके गुनाह और नाजायज शराब गालनेके बारेमें बड़ा अग्र हो गया है। ऐसे समय राहत और दयाके बदले कड़ी सजाका आदर्श सामने रखकर न्यायासन काम करें, तो वह अचित और कदरके लायक माना जायगा। कानून ऐसा तो हरगिज नहीं कहता कि पहले गुनाहके लिये सजा हो ही नहीं सकती। पहले गुनाहके लिये कुछ हद तक अदरता बताना स्वाभाविक है और उस विषयमें क्या करना और क्या न करना यह न्यायाधीशके अधिकारकी बात है। आजकी हालतोंमें शहरों और बड़े गांवोंमें चोरीसे शराब पीने, नाजायज शराब बनाने या लाने-ले जानेके गुनाह खूब बढ़ गये हैं। यह कालाबाजार और खाने-पीने वर्गकी चीजोंमें मिलावट करके जनताको ठगने जैसा ही एक सामाजिक अपद्रव माना जायगा। उसका सामना करनेके लिये राज्यके ये तीनों मुख्य विभाग साथ मिलकर काम करें यह जरूरी और स्वाभाविक भी होगा। क्योंकि, जैसा हमने ऊपर देखा, जिसमें कोजी जैसे-वैसे कानून या शासनतंत्रकी नीतिका सवाल नहीं है, बल्कि भारतके विधानने अिन तीनों विभागोंके लिये आज्ञारूप मानी जा सकनेवाली जो शराबबंदीकी नीति निर्दिष्ट की है, उस पर अमल करके लोककल्याण साधनेकी बात है।

शासन और न्याय अिन दो विभागोंको अलग करनेके सुन्दर आरम्भके लिये हम बम्बई राज्य तथा उसकी हाजीकोर्ट और मंत्रि-मंडलको बधायी दें और साथ ही यह आशा रखें कि अब न्याय-विभागके कामकी ऐसी व्यवस्था की जायगी, जो हमारी जनताको अनुकूल पड़े और उसमें अंग्रेजी पद्धतिके जो कुछ दोष मौजूद हैं वे दूर कर दिये जायंगे। वकील लोगोंका फर्ज है कि वे अिन दोषोंके बारेमें जनमतको शिक्षित वनावें। अदालतोंकी मियाद बढ़ानेकी आदत, खर्चीलापन और अंग्रेजी भाषाका अनुचित अपुयोग ये दोष तो तुरन्त ध्यानमें आने जैसे हैं। स्वतंत्र अदालतें अब अिन दोषोंको सुधारने लगे तो बड़ा अच्छा हो।

८-७-५३
(गुजरातीसे)

मगनभाओ देशाओ

विचारकी रसीद

भूदान और संपत्ति-दानके सिवा और कोजी दान न लेनेकी मैंने मर्यादा रखी है। हम एक महान समस्या हल करने जा रहे हैं। अुसी पर हमें अेकाग्र होना चाहिये। चंदेके तौर पर पैसा लेना तो मैं खतरनाक मानता हूँ। गोदान भी हमारे कामकी चीज नहीं है।

जमीनका छठा अंश तो हम मांगें; फिर भी जो दिया जाय उसका हम अिनकार नहीं कर सकते। हां, जो बिलकुल ही कम दे वह नहीं लेना चाहिये; क्योंकि अुसमें देनेवालेकी बेअिज्जती होती है।

संपत्ति-दान भी बहुत सावधानीसे लेना चाहिये, क्योंकि वह जिंदगी भर देनेकी चीज है। अुत्साहमें आकर कोजी दान-पत्र लिख दे और बादमें अमल न करे, तो ऐसे दान-पत्रसे वातावरण विगड़ सकता है। असलिये पूरे विश्वाससे और कुटुंबके सलाह-मशविरेसे जो संपत्ति-दान-पत्र लिख दे, अुसीको स्वीकार करना चाहिये।

भूमि-दान देनेवाला योग्य प्रतिग्रहीताका नाम सुझा सकता है, पर साधारणतया सार्वजनिक सभामें बंटवारेका हमारा जो तरीका है, अुसी तरह बंटवारा करनेका रिवाज अच्छा है। बिना किसी शर्तके दान देना दाताके लिये अच्छा है।

हमारे कामका स्वरूप तो ऐसा है कि सम्यक् विचार समझा दें और रसीदके रूपमें भूदान प्राप्त करें।

विनोबा

८५ वीं चरखा-द्वादशी

(भादों वदी १२, संवत् २००९)

[ता० १७-७-५३ से ता० ४-१०-५३ तक ८० दिनका कार्यक्रम]
भादों वदी १२ पूज्य श्री गांधीजीका जन्मदिन है। अस वर्ष चरखा-द्वादशीका कार्यक्रम ता० १७-७-५३ को सुबह साढ़े सात बजे प्रार्थनासे शुरू होगा।

बीस वर्ष पहले अस कार्यक्रमकी मूल योजना यहांसे शुरू हुयी थी। पू० बापूजीने अुसे स्वीकारा तथा प्रोत्साहन दिया था। चरखा-संघ और भारतके हरअेक प्रान्तने असका अनुकरण किया। चरखेका वातावरण बनानेमें अस योजनाने अच्छा हाथ बंटाय।

हर वर्ष पू० बापूजी अपने प्रेरणादायी संदेश पहुंचाते रहे और समारम्भके समय किसी न किसी अग्रगण्य नेताको भेजते रहे। अुस प्रसंगके अुनके कुछ अुद्गार और संदेश नीचे दिये जाते हैं।

पू० गांधीजीकी ७०वीं वर्षगांठके समयके कार्यक्रमके संबंधमें आये अुसे अुनके पत्रमें से:

चि० नारणदास,

*

*

*

यदि वहां वातावरण हो तो हरिजन-बस्तीमें जाकर हरिजनोंकी सेवा आदि कार्य भी शुरू करने जैसा है। लेकिन यज्ञमें लगे अुसे लोगोंको छोड़कर कोजी और मिल जाय तो ही यह काम किया जाय। सारे काम अेक ही समाज करने बैठे तो सभीके विगड़नेकी संभावना रहती है। असलिये तुम्हारा अनुभव जिसकी गवाही न दे, वैसा कोजी काम न करना। मैंने तो विविधताकी दृष्टिसे ही यह सुझाया है। जैसे चरखा-द्वादशीका हेतु तो अुन दिनों चरखेका ही ध्यान करनेका है।

सेगांव, वर्षा,
१९-७-३८

बापूके आशीर्वाद

चरखा-संघने जयंती मनानेका निर्णय कर लिया है। असका काम होगा खादीके लिये चन्दा अिकट्टा करना, सूत कातना और सूत अिकट्टा करना। असके लिये चरखा-संघके सामने नारणदास गांधीका अुदाहरण है। वे कजी सालोंसे सूत और चन्देकी रकम अिकट्टा-करनेकी प्रतिज्ञा लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। हर साल अुन्हें अुत्तरोत्तर सफलता मिलती जाती है। कोजी कारण नहीं कि चरखा-संघको भी ऐसी ही सफलता न मिले। बृढ़ संकल्पवाले कार्यकर्ता मिल सकें, तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। खादीके बिना लोगोंको नंगे रहनेका प्रसंग आ सकता है। अस प्रसंगको टालनेका काम यदि कोजी कर सकता है तो वह चरखा-संघ ही है।

मो० क० गांधी

पूज्यश्री बापूजीका ता० ३१-८-४४ का पत्र:

चि० नारणदास,

(कस्तूरबा स्मारक निधि) पीन करोड़की निधि अिकट्टी हो गयी है। असका तो जो होना होगा सो होगा। असमें से तुम्हारे अपुयोगमें कितनी आ सकेगी, यह मैं नहीं जानता। लेकिन तुम्हारा काम तो, जो अस निधिके मूलमें हो, तुम्हारी अपनी पद्धतिके अनुसार चलते रहना चाहिये। यह बात अुन लोगोंको समझ लेनी चाहिये, जो तुम्हें चरखा-द्वादशीकी शैलीमें हमेशा मदद देते रहे हैं; और अिसे यदि वे समझ सकेंगे तो जैसे तुम्हें हमेशा मदद देते रहे हैं, वैसे अस वक्त भी देंगे। जहां तुम्हें लगे कि अैसे सहायकोंके लिये मेरे अभिप्रायकी जरूरत रहेगी, वहां तुम अस पत्रका अिस्ते-माल कर सकते हो। कस्तूरबा-निधिका अर्थ अुलटा हो और अुससे तुम्हारे कामके विस्तारमें रुकावट पैदा हो, तो मुझे

जरूर दुःख होगा। मैं तो इस निधिका सदुपयोग तभी मानूंगा, जब उसके द्वारा चरों और तुम्हारे जैसे कामका विस्तार हो।
सेवाग्राम, वर्धा (सी. पी.)
३१-८-४४

बापूके आशीर्वाद

पू० गांधीजीकी ७६ वीं वर्षगांठके अवसर पर आयोजित कार्यक्रमके बारेमें आया हुआ अनूका संदेश:

चि० नारणदास,

तुम्हारी वार्षिक रिपोर्ट ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ। अभी मैंने कुछ लिखना शुरू नहीं किया। केवल बीमारोंको तीन खत लिखे हैं। लेकिन दरिद्रनारायण जैसा बीमार इस दुनियामें कोभी नहीं है। तुम तो उसके अनन्य भक्तोंमें से हो। मेरी जयंतीके निमित्तसे चरखा-द्वादशी मनाते हो और हर साल अपनी सेवाको कठोर बनाते जाते हो। इस साल भारी कसौटी है। श्रीश्वर करे तुम्हें उसमें सफलता मिले। जेल-महलमें इस समय मार्क्स और उसके सम्बन्धमें उसके महान प्रयोगोंका जो साहित्य मेरे हाथमें आया उसे पढ़ गया हूँ। कहां वे प्रयोग और कहां यह चरखा? वहां भी हमारे यहांकी तरह सारी जनताको यज्ञमें बुलाया जाता है। पर यहां और वहांमें पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिणका भेद है। कहां हमारा चरखा और कहां वहांके भाप और बिजलीसे चलनेवाले यंत्र! जितना होने पर भी मुझे बीरबहूटीके जैसी चरखेकी गति प्रिय है। चरखा अहिंसाका प्रतीक है। और अन्तमें विजय तो अहिंसाकी ही होनेवाली है। लेकिन हम उसके पुजारी ही यदि शिथिल होंगे, तो खुद भी लजायेंगे और अहिंसाको भी लज्जित करेंगे। तुम्हारी प्रवृत्ति उत्तम है। अब उसमें नवीनता लानी चाहिये। चरखेका भी शास्त्र है—जिस तरह यंत्रका है। चरखेका 'टेकनिक' अभी हम नहीं बना पाये। उसके पीछे गहरा अभ्यास चाहिये।

जिस प्रकार बिना श्रद्धाका ज्ञान व्यर्थ है, उसी प्रकार बिना ज्ञानकी श्रद्धा अंधी है।

जूह, २०-५-४४

बापूके आशीर्वाद

उत्तर प्रदेशके मुख्य कार्यकर्ताओंके साथ हुई बातचीतमें पूज्यश्री बापूजीने कहा था कि मैं तो आपके सामने व्यापक कताओका ही कार्यक्रम रखूंगा। डॉक्टरोंकी चेतावनी और सलाहके कारण मैंने स्वयं कुछ समयके लिये कातना छोड़ दिया था, लेकिन नारणदास गांधीकी खबर आते ही मैंने फिर कातना शुरू कर दिया है और वह मेरे हाथको पक्षाघात न हो तो कभी छूटनेवाला नहीं है।

चि० नारणदास,

मुझे अपनी जयंतीका भान ही नहीं है। मैं तो उसे केवल चरखा-जयंतीके रूपमें ही जानता हूँ। तुम भी उसमें जो जितना रस लेते हो वह मेरे रिश्तेदार होनेके नाते नहीं, बल्कि इसलिये कि तुम्हें भी चरखा मेरे जितना ही प्यारा है। भगवान करे तुम उसे अपने आसपास कुछ अधिक गति दे सको। आजके शिथिल वातावरणमें यह काम मुश्किल है। नीरस भी माना जा सकता है। लेकिन दृढ़ श्रद्धा मुश्किलको आसान बना देती है और जो नीरस लगता है, उसे सरस बना देती है। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे वायुमंडलको चरखेकी शक्ति देखनेकी क्षमता प्रदान करे।

सेमांव, वर्धा,
२८-९-३६

बापूके आशीर्वाद

पू० गांधीजीकी ७४ वीं वर्षगांठके अवसर पर अनूकी ओरसे आया हुआ संदेश:

चि० नारणदास,

यह अवसर ही ऐसा है जब गरीब-अमीर, छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष सबको देखके लिये कातना ही चाहिये। चरखा न

हो तो हम सबके लिये नगे फिरनेकी नीवत आनेकी पूरी संभावना है!

सेमांव, वर्धा,
१५-७-४२

बापूके आशीर्वाद

इस वर्षके समारंभके लिये सौराष्ट्रके भूषण भाओश्री वैकुण्ठराय लल्लुभाओ मेहताको निमंत्रण भेजा गया था, जिसे अन्होंने मंजूर कर लिया है। वे अखिल भारत खादी ग्रामोद्योग बोर्डके अध्यक्ष हैं, जिस दृष्टिसे अनूका आगमन बड़ा उपयोगी होगा।

कातनेवाले अिन दिनों अपनी अधिक शक्ति और समय देकर कातनेका संकल्प करें—सूतकी गूडियां दानमें दें और दाता लोग दरिद्रनारायणकी थैलीमें ८० सिक्के दें। इस थैलीसे सौराष्ट्रमें अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियां चल रही हैं।

राष्ट्रीय शाला, राजकोट

१-७-५३

(गुजरातीसे)

नारणदास गांधी

परोक्ष साक्षेदारी

एक पत्रलेखकको मेरे ता० २७-६-५३ के 'हरिजन' में छपे 'मजदूरोंके लिये सुख-सुविधायें' नामक लेखमें से यह सूचना पसन्द आयी है: "राजनैतिक दलों और मजदूर-संघोंको ऐसा कोओ रास्ता खोजना चाहिये, जो बुद्योगोंमें मजदूरोंको फिरसे पूंजी-पतियोंके संयुक्त साक्षेदार बना दे। आज तो पूंजीपति ही कानून और अमल दोनोंमें बुद्योगोंके एकमात्र स्वामी बने हुये हैं। यह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। मजदूरों और पूंजीपतियोंको बुद्योगोंमें संयुक्त साक्षेदार होना चाहिये और परोक्ष पूंजीपतित्व या साक्षेदारी (शेअर-होल्डिंग) की बुराओ मिटनी चाहिये।" और जिसे सिद्ध करनेका रास्ता बताते हुये वे लिखते हैं:

"आप ता० २७-६-५३ के 'हरिजन' में छपे अपने 'मजदूरोंके लिये सुख-सुविधायें' नामक लेखके आखिरी पैरेमें कहते हैं कि 'साक्षेदारीकी प्रथा मिटनी चाहिये'। आप ठीक कहते हैं, लेकिन वह व्यवस्थित ढंगसे मजदूरोंके हाथमें जानी चाहिये। मजदूरको नकद पैसेके रूपमें बीनस देनेके बजाय शेअरके रूपमें देना चाहिये।

"आजके कानूनमें ऐसा सुधार किया जाय कि हरएक मजदूरकी एक वर्षकी सन्तोषजनक नौकरीके बाद उसे एक शेअर अनिवार्य रूपसे देना ही चाहिये। इस तरह २५ सालकी नौकरीके बाद उसके जैसे २५ शेअर हो जायंगे और नौकरीसे निवृत्त होनेके बाद उसे डिविडेन्ड (मुनाफे)के रूपमें अच्छी रकम मिलती रहेगी।

"जिस प्रक्रियासे मालिकीका हक परोक्ष पूंजीपतियोंके हाथसे निकलकर प्रत्यक्ष काम करनेवाले मजदूरोंके हाथमें चला जायगा; और मजदूरोंके कंधों पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ जायगी।"

मुझे कहना चाहिये कि अपरोक्त लेख लिखते समय मेरे मनमें यही बात थी। और जैसा कि मैंने उस लेखके अन्तमें कहा था, जिससे संबंध रखनेवाला बुदाहरण देकर जिस विचारको मैं यहां आगे बढ़ाता हूँ:—

बम्बई राज्यका अभी हालका काश्तकारी कानून इसी सिद्धान्त पर रचा गया है कि रयतवारी प्रथाके मातहत खातेदार कहे जानेवाले व्यक्ति या जमीन-मालिकके साथ जमीन पर उस आदमीका भी हक होगा, जो उस पर काश्तकारकी तरह काम करता है। जमीन-मालिकका तो कानूनके मुताबिक जमीन पर केवल मालिकी हक ही है, जिसे आजकी अर्थ-व्यवस्थामें किसी तरह बुत्पादक तत्त्व नहीं कहा जा सकता; जब कि काश्तकार सचमुच संपत्ति पैदा करता है और जमीनको मूल्यवान बनाता है।

असके बिना मालिकी हक बेकार है और आधिक दृष्टिसे उसका कोई महत्व नहीं है। मालिकी हक तो आजकी प्रचलित अर्थ-व्यवस्था द्वारा पैदा की हुयी अंक कानूनी तरकीब है, जब कि जमीनकी जुतायी अंक जीता-जागता सत्य है, जिसके बिना कानूनी तरकीबका कोई अर्थ और महत्व नहीं रह जायगा। असलिये सामाजिक न्यायके नाम पर दरअसल मेहनत करनेवालेका भी जमीन पर कोई निश्चित कानूनी हक होना चाहिये। बंबयीकी धारासभा इसी बुनियादी सिद्धान्तके आधार पर काश्तकारी कानून बनाती है।

अब इस सिद्धान्तको हम औद्योगिक संबंधों पर लागू करें। इससे हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं?

अधोगपति किसी अधोगसे संबंध रखनेवाले ज्ञानका अपयोग करनेकी अपनी योग्यताके बल पर लिमिटेड कंपनी खोलनेकी तरकीब निकालकर पूंजी अिकट्टी करता है; इस तरह पाया हुआ पैसा कारखाना खोलनेमें लगाता है और साझेदारों (शेअर-होल्डरों) के नाम पर कंपनी अेक्टकी रूसे दरअसल उसका मालिक बन जाता है। थोड़ेमें, वह पूंजीका मालिक होता है और उसकी ताकत और कीमतके बल पर कारखाना चलानेके लिये कुशल और अकुशल मजदूरोंको काम पर लगाता है। सच पूछा जाय तो देशकी अर्थ-व्यवस्थामें इस कारखानेका तब तक कोई मूल्य नहीं है, जब तक मजदूर उसे चलाकर संपत्ति पैदा नहीं करते। इस तरह, जैसा कि गांधीजीने हमें बार-बार कहा था, केवल पूंजीपति ही नहीं बल्कि मजदूर भी संपत्ति पैदा करनेकी प्रक्रियाके अंग हैं, क्योंकि दोनों जरूरतकी चीजोंके रूपमें संपत्ति पैदा करनेमें हाथ बंटते हैं। असलिये पूंजीपति और मजदूर दोनों कारखानेके संयुक्त मालिक होने चाहिये। न्यायका यह तकाजा है कि उत्पादनके अिन दोनों अंगोंके औद्योगिक संबंधोंका आधार यही बुनियादी सिद्धान्त हो।

लेकिन आज हम क्या देखते हैं? शेअर-होल्डर ही अकेले कारखानेके कानूनी मालिक हैं, हालांकि वे प्रत्यक्ष उत्पादनके काममें कोई हिस्सा नहीं लेते। परोक्ष जमींदारोंकी तरह वे भी पूंजीके परोक्ष मालिकोंके नाते काम कर सकते हैं।

और अुनके पास बचाने, अधोगमें लगाने और इस तरह डिविडेन्ड वगैराके रूपमें बिना मेहनतके बढ़ानेके लिये यह अतिरिक्त पूंजी आयी कहाँसे? यह अंक बड़ा सवाल है। यहां तो मैं अितना ही कहकर संतोष करूंगा कि जमीनकी तरह समाज द्वारा पैदा की हुयी पूंजी या अतिरिक्त मूल्य पर समाजका अधिकार है। असलिये वह अंक सामाजिक नीति और राष्ट्रीय आदेशके अनुसार वापस संपत्तिके उत्पादनमें ही लगायी जानी चाहिये। जिसके पास अुस पूंजीका हिस्सा हो, वह खुद अपने ही अपयोगमें अुसे ला सकता है; वर्ना अुसे बैंकमें जमा करा देना चाहिये। अैसे सारे बैंकों पर जनताकी तरफसे और जनताके ट्रस्टीके नाते राज्यका अधिकार होगा। बैंक जनताकी आधिक स्थितिको पुसाये, अितना ब्याज समय-समय पर इस रकम पर दे सकती है। लेकिन अगर हम समाजमें स्वस्थ और अच्छे औद्योगिक संबंध कायम करना चाहते हैं, तो कोई भी पूंजीपति किसी अधोगमें परोक्ष साझेदार या शेअर-होल्डर नहीं होना चाहिये।

अब हम मजदूरोंका विचार करें। मजदूर भी अपनी मेहनतके जरिये संपत्तिके उत्पादनमें हिस्सा लेता है, लेकिन अुसे आजकी अर्थ-व्यवस्थामें शेअर-होल्डरके नाते मान्यता नहीं मिलती। इसीलिये मालिक और मजदूरका द्वैत और मजदूरकी प्रथा जन्म लेती है, जिससे औद्योगिक संबंध पेचीदा हो जाते हैं और मालिकों या पूंजीपतियोंका पलड़ा भारी हो जाता है। यह द्वैत अन्यायपूर्ण है और कानूनन मिटा दिया जाना चाहिये। इस दृष्टिसे देखने पर

मालूम होता है कि कंपनी-कानून अैसे औद्योगिक युगकी अपज हैं, जब अधोगपतियों और पूंजीपतियोंका ही बोलबाला था और शैतान सबसे कमजोरको अपना शिकार बनानेके लिये आजाद था। वह युग आज अपनी जन्मभूमि युरोपमें भी खतम हो रहा है। भारतको अुसका पुनरावर्तन नहीं करना चाहिये और अुसे अत्यन्त पुरानी चीज मानकर छोड़ देना चाहिये। अुसे अंक नयी दिशा अपना कर इस विषयमें बुनियादी परिवर्तन करनेकी तैयारी करनी चाहिये — अैसी दिशा जो यह जरूरी मानती है कि पूंजीपति और मजदूर दोनों समान हकसे अधोगके मालिक हों। कानूनमें भी अैसा सुधार किया जाना चाहिये। हमारी अर्थ-रचनाके औद्योगिक क्षेत्रसे संबंध रखनेवाली समस्याको इस आधार पर हल करना चाहिये और सरकार तथा मजदूर-संस्थाओंको असके लिये कामकी अंक अनुकूल योजना बनानी चाहिये।

४-७-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभायी बैसायी

अस्पृश्यताका नाश : हमारा अंकमात्र ध्येय

पूज्य गांधीजीके निधनके पश्चात् तथा स्वराज्य आनेके बाद यों लगभग सभी रचनात्मक कार्योंकी तरफ लोकनेताओं तथा जनसेवकोंका ध्यान पहलेके जैसा नहीं रहा। यह दुर्भाग्यकी बात है। अस्पृश्यताके बारेमें अंक इस गलत धारणासे भी बहुत-कुछ शिथिलता आ गयी है कि चूंकि भारतीय संविधानने अस्पृश्यताका सब प्रकारसे अन्त कर दिया है, और केन्द्र-सरकार तथा राज्य-सरकारें तो हरिजन-कल्याणका कार्य कर ही रही हैं, असलिये अब हम हरिजन-सेवकोंको कुछ खास करनेका नहीं रहा है। गांधीजी और ठक्करबापाके मार्गदर्शनमें जिन कार्यकर्ताओंने शिक्षा पायी थी, वे तो वैसी ही लगन और परिश्रमके साथ काम कर रहे हैं। किन्तु कुछेक अन्य कार्यकर्ताओंका ध्यान राजनैतिक, खासकर अंकके बाद दूसरे आनेवाले चुनावोंके कामकी ओर ही अधिक आकृष्ट देखनेमें आया है। प्रायः हरअंक रचनात्मक क्षेत्रमें शुद्ध धर्म-दृष्टिसे काम करनेवाले लोकसेवक देशकी बदली हुयी परिस्थितियोंमें बहुत कम देखनेमें आ रहे हैं, फिर भी हताश होनेका कोई कारण नहीं। जितने भी कुछ कार्यकर्ता अस्पृश्यता-निवारणके महत्त्वको गहराअीसे अनुभव करते रहे हैं, अुनकी सेवा-साधना अवश्य सफल हुयी है और आगे भी होगी, असमें संदेह नहीं।

वैसे तो कितने ही पिछड़े वर्गों और पिछड़ी जातियोंके अनेक जटिल प्रश्न आज हमारे स्वतंत्र राष्ट्रके सामने हैं। पर हरिजनोंका प्रश्न केवल 'पिछड़ेपन' का ही प्रश्न नहीं है। जिन अनेक सामाजिक व नागरिक नियोग्यताओंके वे आज भी शिकार बने हुअे हैं, वे नियोग्यताअें अन्यथा पिछड़ी हुयी दूसरी जातियोंमें नहीं मिलती हैं। अस्पृश्यताका यह घातक प्रश्न तो देशमें और विदेशोंमें लज्जासे हमारा सिर आज भी नीचा कर रहा है। गांधीजीको हिन्दूधम पर लगे इसी महाकलंकको धोनेके लिये अपने प्राणोंकी भी बाजी १९३२ में लगा देनी पड़ी थी।

अस्पृश्यता-निवारण या नियोग्यता-निवारण केवल कानूनके बल पर या राज-दण्डके भयसे संभव नहीं। कानून भी अंतमें कुछ सहायक तो हो सकता है, पर असलमें तो सबणोंके हृदय-परिवर्तनके द्वारा ही अस्पृश्यताका संपूर्ण निवारण संभव है। इस बातसे अिन्कार नहीं किया जा सकता कि गांधीजीके घोर तप तथा स्व० ठक्करबापा द्वारा संचालित हरिजन-सेवक-संघके निरंतर प्रयत्नों, और कालकी गतिसे भी, वातावरणमें कुछ खासा परिवर्तन हुआ है। किन्तु कोई कारण नहीं कि अितने मात्रसे आत्मसंतोष करके हम बैठ जायं।

केन्द्र-सरकार तथा राज्य-सरकारें परिगणित जातियोंको सबके समान स्तर पर लानेके जो अनेकविध प्रयत्न कर रही हैं, अुनके

प्रति अचित्त संतोष प्रकट करते हुये तथा अउन प्रयत्नोंको अधिक जोरदार बनानेके लिये सरकारोंको प्रेरित करते हुये, पर अउन्हीं पर निर्भर न रहकर, हम हरिजन-सेवकोंको अपने खुदके कर्तव्यों और प्रयत्नोंके प्रति अधिक-से-अधिक कृतसंकल्प और जाग्रत रहना है, क्योंकि, अस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजन-सेवाकी जिम्मेदारी मूलतः हिंदू-समाज पर आती है।

ग्रामोंमें और अनेक कस्बोंमें भी, किसी-किसी शहरमें भी, अस्पृश्यताके भयंकर रूप आज भी सुनने व देखनेमें आते हैं। कहीं पर अउनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, कहीं-कहीं अउनके झोंपड़ोंमें आग लगा दी जाती है और अउन्हें कत्ल तक कर दिया जाता है। अउनकी भूमिहीनताके कारण तो अउनकी बदतर हालत है ही। जहां भी हरिजनों पर अैसे-अैसे अत्याचार होते हुये सुने और देखे जायं, वहां तुरन्त हरिजन-सेवक दौड़कर अउनके निवारणका प्रयत्न करें। सेवाभावी वकील भी अउनके मामलोंमें 'बुद्धिदान' देकर बगैर फीस लिये पैरवी करें।

सार्वजनिक कुओं और दूसरे जलाशयोंको खुलवाने, देव-मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानोंमें सबके समान हरिजनोंका प्रवेश कराने आदिका कार्यक्रम तो हरिजन-सेवकोंको पूरे जोरसे चलाना ही चाहिये।

म्मुनिसिपैलिटियों और ग्राम-पंचायतों पर जोर डालकर नगर-सफाई व ग्राम-सफाई करनेवाले हरिजन-कर्मचारियोंके काम और साधनमें सुधार और अउनके लिये घरोंकी, पानीकी व रोशनी अित्यादिकी आवश्यक व्यवस्था तत्परतापूर्वक करानी चाहिये।

आचार्य विनोबाके भूमिदान-आन्दोलनसे भी पूरा लाभ अउठाना चाहिये। भूमिदान-यज्ञके सिलसिलेमें जो लोकनेता और सर्वोदयी कार्यकर्ता गांव-गांवमें पैदल यात्रा कर रहे हैं, अउनका ध्यान हरिजन-समस्या पर अवश्य जाता होगा। तो फिर अउनको यात्राओंसे लाभ क्यों न अउठाय जाय? हरिजन-सेवक स्थानीय भूमि-वितरण-समितियोंसे संपर्क स्थापित करें और आचार्य विनोबाजी द्वारा दिये हुये वचनके अनुसार अेक-तिहाजी खेतीयोग्य भूमि, और जहां संभव हो वहां बँल भी, हरिजनोंको दिलानेका प्रयत्न करें। जहां घोर जल-कष्ट देखनेमें आये वहां 'कूप-दान' करनेके लिये भी लोगोंको प्रेरित करें।

संघके गत वार्षिक अधिवेशनमें जो कभी महत्त्वपूर्ण निश्चय हुये थे अउन्हें भी कार्यान्वित करना है। संघकी मुख-पत्रिका "हरिजन-सेवा" के काफी ग्राहक बनाकर अउसका अधिक-से-अधिक प्रचार करना चाहिये। और भी कितने ही अैसे कार्य हैं जिनको अउत्साह और निष्ठासे हाथोंमें लेकर हरिजन-सेवक-संघके कार्यकर्ता अस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजनोंकी सामाजिक और आर्थिक अुन्नति कर सकते हैं। संक्षेपमें कहा जाये तो गांधीजी और बापाजीके छोड़े हुये अधूरे काम पर हमारी निरंतर दृष्टि रहे। अस्पृश्यताका जल्द-से-जल्द नाश कर देना ही हम हरिजन-सेवकोंका अेकमात्र ध्येय हो।

अ० भा० हरिजन सेवक-संघ
हरिजन-निवास, दिल्ली

वियोगी हरि

हमारा नया प्रकाशन
द्विवेक और साधना

लेखक : केदारनाथ
संपादक

किशोरलाल मशरूवाला : रमणीकलाल मोदी

कीमत ४-०-०

डाकखर्च ०-१२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद - ९

www.vinoba.in

खेदजनक निर्णय

अभी गत सप्ताह आगरामें अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकके साथ अउत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारी समितिकी बैठक हुअी थी। अखबारोंमें आये हुये समाचारोंसे मालूम होता है कि अउत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी समितिकी अिस बैठकने यह निर्णय किया है कि भाषाके प्रश्न पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके ३० मजी, १९५३ के सरकुलरका अउत्तर प्रदेशकी भाषा-नीति पर कोअी असर नहीं होगा और अिस समितिका पहले लिया हुआ यह निर्णय कायम रहेगा कि अउत्तर प्रदेशकी राज्य-भाषा सिर्फ हिन्दी ही मानी जाय।

अ० भा० कांग्रेस कमेटीके अपर्युक्त सरकुलरमें हिन्दीके महत्त्व पर जोर दिया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि अपने-अपने क्षेत्रमें प्रादेशिक भाषाओंका भी विकास होना चाहिये तथा अुर्दूको अुचित स्थान दिया जाना चाहिये। सरकुलरके शब्दोंमें — "यह मानना चाहिये कि अुर्दू भारतकी भाषा है, भारतमें अुसका जन्म और विकास हुआ और देशके काफी लोग अुसे लिखते-बोलते हैं।"

अिसी सिलसिलेमें यह खबर भी पढ़नेमें आयी कि अउत्तर प्रदेश भाषा-समितिके अेक मेमोरेन्डम तैयार किया है, जिसमें अुर्दूको अउत्तर प्रदेशकी दूसरी राज्य-भाषाकी तरह स्वीकार करानेके लिये जो आन्दोलन हो रहा है अुस पर 'बड़ी चिन्ता' प्रगट की है। यह मेमोरेन्डम कांग्रेस-अध्यक्षको दिया जायगा। अुसमें कहा गया है कि अुर्दूको राज्य-भाषाकी मान्यता दिलानेकी यह कोशिश दोनों समाजोंको अेक-दूसरेके नजदीक लानेके बजाय अुनके बीचका भेद और ज्यादा बढ़ायेगी।

यह बड़ी दुर्भाग्यकी बात है कि अउत्तर भारतमें और अउत्तर प्रदेशमें, जहां अुर्दू वर्ग और सम्प्रदायके परे जनताकी सामान्य भाषा है, लोगोंको अुर्दूको मुस्लिम भाषा माननेकी गलत सिखावन दी गयी है। यही चीज है जिससे भाषाके सरल और सीधे सवालमें साम्प्रदायिकताका रंग आ जाता है और व्यर्थका झगड़ा और द्वेष अुत्पन्न होता है। कांग्रेस हमेशा भारतके लिये अेक अैसी सर्व-सामान्य भाषाके पक्षमें रही है, जो हिन्दी और अुर्दूके स्वाभाविक मेलसे बना हुआ अुनका सरल रूप होगी। कांग्रेसकी अिस रायकी हमारे संविधानमें, जहां हमारी भावी भाषा-नीतिका स्पष्टीकरण हुआ है, भरपूर ताअीद हुअी है। हिन्दी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल आदिके साथ अुर्दू भी हमारे संविधानकी अेक स्वीकृत भारतीय भाषा है (देखिये परिशिष्ट - ८)। तो जहां वह बोली जाती है — और अिसमें कोअी शक नहीं कि अउत्तर प्रदेशमें काफी लोग अुसे बोलते हैं — वहां अुसे मान्यता न देना संविधानके प्रतिकूल है और कांग्रेसकी विचारधाराके भी प्रतिकूल है। अिसलिये अउत्तर प्रदेश कांग्रेसका अुर्दूका यह विरोध अत्यन्त खेदजनक है। हम अुम्मीद करते हैं कि जिन लोगोंका अिससे संबंध है, वे बुद्धिमान्नीसे काम लेंगे और कांग्रेसने तथा राष्ट्र-पिताने हमारे लिये जो सही भाषा-नीति निर्धारित की है, अुसका विरोध करके व्यर्थ ही अुभङ्गने-वाली सांप्रदायिक भावनाओंको पनपनेका नया मौका नहीं देंगे।

११-७-५३

(अंग्रेजीसे)

मगनभाअी देसाअी

विषय-सूची	पृष्ठ
ग्राम-शक्तिका निर्माण	विनोबा १५३
छोटे समाजकी खूबियां	विल्फ्रेड वेलॉक १५४
न्याय और शासन-विभाग	मगनभाअी देसाअी १५६
८५ वीं चरखा-द्वादशी	नारणदास गांधी १५७
परोक्ष साझेदारी	मगनभाअी देसाअी १५८
अस्पृश्यताका नाश : हमारा अेकमात्र ध्येय	वियोगी हरि १५९
खेदजनक निर्णय	मगनभाअी देसाअी १६०
टिप्पणी :	
विचारकी रसीद	विनोबा १५७